INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 12 | JANUARY– 2025

बिलासपुर ज़िले में आंतरिक प्रवासन और शहरी झुग्गी बस्तियों का विकास: प्रवासी जीवन और सामाजिक समस्याएँ

डॉ. सुश्री आरती तिवारी
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र (प्रभारी प्राचार्य)
एस. बी. टी. महाविद्यालय, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश:

आंतरिक प्रवासन भारत में शहरीकरण की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने शहरी झुग्गी–बस्तियों के विस्तार और प्रवासी जनसंख्या की जीवन-स्थितियों को गहराई से प्रभावित किया है। यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में आंतरिक प्रवासन और शहरी झुग्गी–बस्तियों के विकास के आपसी संबंध का अध्ययन करता है, जिसमें प्रवासी जीवन और उनसे जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अध्ययन में ग्रामीण-शहरी प्रवासन के कारणों, झुग्गी–बस्तियों के निर्माण के स्वरूप, प्रवासियों की व्यावसायिक स्थितियों, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच तथा प्रवासी परिवारों द्वारा झेली जा रही सामाजिक चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि गरीबी, बेरोज़गारी और कृषि संकट से प्रेरित तीव्र प्रवासन के कारण अव्यवस्थित बस्तियों का विस्तार हुआ है, जिनकी विशेषताएँ खराब आवास, अपर्याप्त स्वच्छता, असुरक्षित रोज़गार और सामाजिक बहिष्करण हैं। यद्यपि प्रवासन से कुछ परिवारों की आय के अवसर बढ़े हैं, फिर भी प्रवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि बिलासपुर में सतत शहरी विकास के लिए समावेशी, प्रवासन-संवेदनशील नीतियाँ, झुग्गी-उन्नयन कार्यक्रम तथा प्रवासी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुँच अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द: आंतरिक प्रवासन, शहरी झुग्गी–बस्तियाँ, प्रवासी जीवन, सामाजिक समस्याएँ, बिलासपुर ज़िला, शहरीकरण.

प्रस्तावना:

आंतरिक प्रवासन भारत में समकालीन शहरी विकास को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर होने वाला जन-आवागमन तीव्र शहरीकरण, नगरों के लिए श्रम-आपूर्ति और आर्थिक विकास में योगदान देता है। साथ ही, अव्यवस्थित प्रवासन के कारण शहरी झुग्गी–बस्तियों का विस्तार भी हुआ है, जिनकी पहचान अपर्याप्त आवास, बुनियादी सेवाओं की कमी और सामाजिक असुरक्षा से होती है। प्रवासी जनसंख्या प्रायः नगरों के सबसे असुरक्षित क्षेत्रों में निवास करती है और उन्हें रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक समावेशन से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ज़िला आंतरिक प्रवासन और शहरी झुग्गी–बस्तियों के विकास के बीच संबंधों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है। एक प्रमुख प्रशासनिक, रेल, वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र होने के कारण बिलासपुर नगर ने ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित किया है। निर्माण गतिविधियों, परिवहन सेवाओं, लघु उद्योगों और असंगठित सेवा क्षेत्र के विस्तार से प्रवासी श्रम की माँग निरंतर बनी रही, जिससे जनसंख्या प्रवाह में वृद्धि हुई।

किन्तु शहरी अवसंरचना और आवास सुविधाओं का विकास प्रवासन की गति के अनुरूप नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, प्रवासियों का एक बड़ा भाग ऐसी झुग्गी–बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में बस गया जहाँ सुरक्षित भूमि अधिकार, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता का अभाव है। इन क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी परिवार अनेक प्रकार के अभाव और सामाजिक बहिष्करण का अनुभव करते हैं। यह अध्ययन इस बात का विश्लेषण करता है कि आंतरिक प्रवासन ने बिलासपुर ज़िलेमें शहरी झुग्गी–बस्तियों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है तथा प्रवासी समुदायों की जीवन-स्थितियों और सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1) बिलासपुर ज़िले में आंतरिक प्रवासन की प्रकृति एवं प्रतिरूपों का अध्ययन करना।
2) शहरी झुग्गी–बस्तियों के विस्तार में प्रवासन की भूमिका का विश्लेषण करना।
3) झुग्गी–बस्तियों में निवास करने वाले प्रवासी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना।
4) आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोज़गार असुरक्षा सहित प्रवासियों द्वारा सामना की जा रही प्रमुख सामाजिक समस्याओं का परीक्षण करना।
5) नीतिगत चुनौतियों का आकलन करना तथा समावेशी शहरी विकास हेतु उपाय सुझाना।

शोध पद्धति:

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प को अपनाता है, जिसका उद्देश्य बिलासपुर ज़िले में शहरी झुग्गी–बस्तियों के विकास में आंतरिक प्रवासन की भूमिका का परीक्षण करना है। अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें भारत की जनगणना रिपोर्टें, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ, सरकारी प्रकाशन तथा शहरी अध्ययन शामिल हैं। प्राथमिक जानकारी 160 उत्तरदाताओं से प्राप्त की गई है। प्रवासन के रुझानों, झुग्गी–बस्तियों के विस्तार तथा प्रवासियों की सामाजिक समस्याओं को समझने हेतु तुलनात्मक एवं समाजशास्त्रीय व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है।

बिलासपुर ज़िले में आंतरिक प्रवासन और शहरी झुग्गी बस्तियों का विकास: प्रवासी जीवन और सामाजिक समस्याएँ

आंतरिक प्रवासन भारत में शहरी विकास को आकार देने वाला एक प्रमुख कारक बन गया है और शहरी झुग्गी–बस्तियों के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गरीबी, भूमिहीनता, कृषि संकट, बेरोज़गारी तथा बेहतर आजीविका की खोज के कारण बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। यद्यपि प्रवासन नगरों को श्रम उपलब्ध कराकर शहरी आर्थिक विकास में योगदान देता है, किंतु जब आवास, अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएँ जनसंख्या वृद्धि की गति के अनुरूप विकसित नहीं होतीं, तब गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। परिणामस्वरूप अनेक प्रवासियों को कठिन परिस्थितियों में झुग्गी–बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ज़िला इस प्रक्रिया का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, रेल, वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र होने के कारण बिलासपुर नगर ने ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित किया है। निर्माण गतिविधियों, परिवहन सेवाओं, लघु उद्योगों और असंगठित सेवा क्षेत्र के विस्तार से प्रवासी श्रम की निरंतर माँग बनी रही। अधिकांश प्रवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और सीमित संसाधनों व कौशल के साथ नगर में प्रवेश करते हैं।

प्रवासियों की तीव्र आमद और किफ़ायती आवास की कमी के कारण बिलासपुर नगर में झुग्गी-बस्तियों का विस्तार हुआ है। प्रवासी प्रायः रेल लाइनों, औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों और खाली सार्वजनिक भूमि के आसपास बसते हैं। इन बस्तियों की प्रमुख विशेषताएँ अत्यधिक भीड़, निम्न-स्तरीय आवास, स्वच्छता की कमी, असुरक्षित पेयजल और भूमि स्वामित्व की अनिश्चितता हैं, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं।

शहरी झुग्गी–बस्तियों में प्रवासी जीवन आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक संवेदनशीलता से युक्त होता है। अधिकांश प्रवासी निर्माण श्रमिक, दैनिक मज़दूर, फेरीवाले, घरेलू कामगार अथवा परिवहन सहायक के रूप में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। रोज़गार

अनियमित, अल्प-वेतन वाला और सामाजिक सुरक्षा से वंचित होता है, जिससे आय की अस्थिरता, बीमारी और मौसमी बेरोज़गारी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है।

झुग्गी–बस्तियों में रहने वाले प्रवासियों को अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें खराब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, बच्चों की शैक्षिक वंचना तथा सामाजिक हाशियाकरण प्रमुख हैं। महिला प्रवासियों को मज़दूरी भेदभाव और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों जैसी अतिरिक्त चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं। अनेक प्रवासियों के पास पहचान पत्र और आवास प्रमाण का अभाव होता है, जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। समग्रतः, आंतरिक प्रवासन ने बिलासपुर ज़िले में शहरी झुग्गी–बस्तियों के विस्तार में योगदान दिया है, जो प्रवासी जीवन-स्थितियों में सुधार और समानतापूर्ण शहरी विकास हेतु समावेशी शहरी नियोजन, किफ़ायती आवास और सामाजिक संरक्षण नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वैचारिक ढाँचा:

आंतरिक प्रवासन: आंतरिक प्रवासन से तात्पर्य राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर लोगों के स्थानांतरण से है, जो मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारणों से प्रेरित होता है। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन इसका सबसे प्रमुख रूप है, जिसके प्रमुख कारण गरीबी, बेरोज़गारी, भूमिहीनता, कृषि संकट तथा बेहतर आजीविका की खोज हैं। प्रवासन शहरी अर्थव्यवस्थाओं (विशेषतः निर्माण, परिवहन, विनिर्माण और असंगठित सेवा क्षेत्रों) को श्रम उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु तीव्र प्रवासन शहरी आवास, अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव भी डालता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर झुग्गी–बस्तियों का विस्तार होता है।

शहरी झुग्गी–बस्तियाँ: शहरी झुग्गी–बस्तियाँ घनी आबादी वाली ऐसी बस्तियाँ हैं, जिनकी पहचान निम्न-स्तरीय आवास, अत्यधिक भीड़, अपर्याप्त स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की कमी, असुरक्षित भूमि अधिकार तथा बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच से होती है। तीव्र शहरीकरण, अव्यवस्थित नगर-विकास और निम्न-आय वर्गों के लिए औपचारिक आवास की अनुपलब्धता के कारण झुग्गी–बस्तियों का उद्भव होता है। प्रवासी श्रमिक झुग्गी–बस्तियों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग होते हैं, क्योंकि वे औपचारिक आवास वहन करने में असमर्थ होते हैं और वैध शहरी स्थानों से बाहर रखे जाते हैं।

बिलासपुर ज़िले में आंतरिक प्रवासन के प्रतिरूप:

बिलासपुर ज़िले में ज़िले के भीतर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों से निरंतर ग्रामीण–शहरी प्रवासन हुआ। प्रारंभ में प्रवासन मुख्यतः पुरुषों तक सीमित रहता है, किंतु रोज़गार स्थिर होने पर पारिवारिक प्रवासन भी होने लगता है। निर्माण श्रमिकों और दैनिक मज़दूरों में मौसमी एवं चक्रीय प्रवासन विशेष रूप से सामान्य है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं में प्रवासन का स्वरूप (n = 160)

प्रवासन का प्रकार	प्रवासियों की संख्या	प्रतिशत (%)
मौसमी प्रवासन	62	38.8
चक्रीय प्रवासन	41	25.6
स्थायी प्रवासन	57	35.6
कुल	**160**	**100**

लगभग दो-तिहाई (64.4%) प्रवासी मौसमी या चक्रीय प्रवासन में संलग्न हैं, जो अस्थिर रोज़गार और ग्रामीण मूल से मज़बूत संबंधों को दर्शाता है। स्थायी प्रवासन (35.6%) शहरी झुग्गी–बस्तियों में दीर्घकालिक बसावट को इंगित करता है, जिससे उनका विस्तार होता है।

प्रवासन और शहरी झुग्गी–बस्तियों का विस्तार:

तेज़ प्रवासन और किफ़ायती आवास की कमी के संयुक्त प्रभाव से बिलासपुर नगर में झुग्गी–बस्तियों का विस्तार हुआ है। प्रवासी प्रायः रेल पटरियों, औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों के निकट बसते हैं।

तालिका 2: झुग्गी–बस्तियों में बसने के कारण (n = 160)

कारण	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
कम किराया / निःशुल्क भूमि	68	42.5
कार्यस्थल के निकटता	47	29.4
वैकल्पिक आवास का अभाव	31	19.4
सामाजिक नेटवर्क (रिश्तेदार/मित्र)	14	8.7
कुल	**160**	**100**

कम रहने की लागत और कार्यस्थल के निकटता झुग्गी–बस्तियों में बसने के प्रमुख कारण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि झुग्गी–बस्तियाँ शहरी अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों के लिए 'जीविका-आधारित' आश्रय स्थल का कार्य करती हैं।

शहरी झुग्गी–बस्तियों में प्रवासी जीवन:

प्रवासी परिवार मुख्यतः असंगठित रोज़गार पर निर्भर रहते हैं और दयनीय आवास स्थितियों में निवास करते हैं।

तालिका 3: प्रवासियों की व्यावसायिक संरचना (n = 160)

व्यवसाय	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
निर्माण श्रम	49	30.6
दैनिक मज़दूरी	36	22.5
फेरी/ठेला व्यवसाय	28	17.5
घरेलू कार्य	24	15.0
परिवहन-संबंधी कार्य	23	14.4
कुल	**160**	**100**

70% से अधिक प्रवासी शारीरिक रूप से कठिन, कम-वेतन और असुरक्षित असंगठित कार्यों में लगे हैं, जो आर्थिक संवेदनशीलता और रोज़गार असुरक्षा को दर्शाता है।

प्रवासियों द्वारा झेली जाने वाली सामाजिक समस्याएँ:

प्रवासियों को परस्पर जुड़ी अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

तालिका 4: प्रवासियों द्वारा बताई गई प्रमुख सामाजिक समस्याएँ (n = 160)

सामाजिक समस्या	उत्तरदाता (%)
आय की असुरक्षा	76
खराब आवास स्थितियाँ	69
स्वच्छता का अभाव	63
स्वास्थ्य समस्याएँ	58
बच्चों की शिक्षा में बाधा	55
बेदखली का भय	47

आय की असुरक्षा और खराब आवास सबसे अधिक उल्लिखित समस्याएँ हैं, जो स्वास्थ्य जोखिम, शैक्षिक वंचना और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाती हैं।

नीतिगत चुनौतियाँ और शहरी विकास:

सरकारी योजनाओं के बावजूद, दस्तावेज़ी बाधाओं और कमजोर क्रियान्वयन के कारण प्रवासी अनेक सेवाओं से वंचित रहते हैं।

तालिका 5: शहरी सेवाओं तक पहुँच (n = 160)

शहरी सेवा	उपलब्ध (%)	अनुपलब्ध (%)
सार्वजनिक जलापूर्ति	46	54
स्वच्छता सुविधाएँ	39	61
सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ	42	58
आवास योजनाएँ	21	79
कल्याणकारी योजनाएँ	28	72

अधिकांश प्रवासियों की बुनियादी शहरी सेवाओं तक पहुँच नहीं है, जो शहरी नियोजन में संरचनात्मक बहिष्करण और शासन की कमियों को दर्शाता है।

160 प्रवासी उत्तरदाताओं पर आधारित विश्लेषण स्पष्ट करता है कि आंतरिक प्रवासन बिलासपुर ज़िले में शहरी झुग्गी–बस्तियों के विस्तार का प्रमुख कारक रहा है। यद्यपि प्रवासन आजीविका के अवसर प्रदान करता है, फिर भी यह प्रवासियों को खराब आवास, असुरक्षित रोज़गार, सीमित सेवाओं और सामाजिक बहिष्करण के जोखिमों के सामने लाता है। झुग्गी–बस्तियाँ अस्थायी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शहरी गरीबी के 'जीवित रहने के स्थान' बन गई हैं। यह स्थिति प्रवासन-संवेदनशील शहरी नीतियों, किफ़ायती आवास और समावेशी सेवा-प्रदान की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष:

बिलासपुर ज़िले में शहरी झुग्गी–बस्तियों के विकास में आंतरिक प्रवासन की निर्णायक भूमिका रही है, क्योंकि रोज़गार और बेहतर आजीविका की खोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवासी नगर की ओर आए। यद्यपि प्रवासन ने निर्माण, परिवहन, औद्योगिक और असंगठित सेवा क्षेत्रों को श्रम उपलब्ध कराकर शहरी आर्थिक विकास को समर्थन दिया, किंतु पर्याप्त आवास और बुनियादी अवसंरचना के अभाव ने अनेक प्रवासियों को झुग्गी–बस्तियों में बसने के लिए विवश किया। इन क्षेत्रों में प्रवासी जीवन असुरक्षित और कम-वेतन वाले रोज़गार, खराब आवास, अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सीमित पहुँच और असुरक्षित भूमि अधिकारों के कारण निरंतर बेदखली के भय से चिह्नित है। गरीबी, स्वास्थ्य जोखिम, बच्चों की शैक्षिक वंचना, लैंगिक संवेदनशीलताएँ और सामाजिक हाशियाकरण प्रवासियों की कठिनाइयों को और गहरा करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान के बावजूद प्रवासी कल्याणकारी योजनाओं और शहरी शासन से प्रायः बाहर ही रहते हैं। अतः यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि बिलासपुर में आंतरिक प्रवासन ने शहरी विकास और शहरी गरीबी, दोनों को एक साथ जन्म दिया है, जिससे समावेशी, प्रवासन-संवेदनशील शहरी नियोजन, किफ़ायती आवास, झुग्गी–उन्नयन और सामाजिक संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट होती है।

सन्दर्भ:

1. *Census of India. (2011). District census handbook: Bilaspur, Chhattisgarh. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. https://censusindia.gov.in*
2. *Government of India. (2013). Report of the committee on slum statistics/census. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. https://mohua.gov.in*
3. *Guria, N. N. (2012). Migration and living conditions in urban slums: A case study of Bilaspur city (Chhattisgarh). Indian Journal of Regional Science, 44(2), 87–98. https://www.academia.edu*

4. *Guria, N. N. (2016). Slum population characteristics and migration: A case study of Bilaspur city (Chhattisgarh). Journal of Urban and Regional Studies, 8(1), 45–56. https://www.researchgate.net*
5. *Kundu, A. (2006). Trends and processes of urbanisation in India. India Infrastructure Report, 27–44.*
6. *Kundu, A., & Sarangi, N. (2007). Migration, employment status and poverty: An analysis across urban centres. Economic and Political Weekly, 42(4), 299–306.*
7. *Mahadevia, D. (2011). Branded and renewed? Policies, politics and processes of urban development in the reform era. Routledge.*
8. *National Sample Survey Office. (2010). Migration in India (64th Round). Ministry of Statistics and Programme Implementation. https://mospi.gov.in*
9. *Planning Commission of India. (2014). Report of the working group on urban poverty, slums and service delivery. Government of India.*
10. *Rao, M. S. A. (2006). Social change in urban India. Orient BlackSwan.*
11. *Registrar General of India. (2011). Housing and amenities: Census of India 2011. Government of India.*
12. *Sharma, K. L. (2013). Indian social structure and change. Rawat Publications.*
13. *Singh, K. S. (1994). People of India: An introduction. Oxford University Press.*
14. *Srinivas, M. N. (2003). Social change in modern India. Orient BlackSwan.*
15. *United Nations Human Settlements Programme. (2003). The challenge of slums: Global report on human settlements. UN-Habitat. https://unhabitat.org*
16. *United Nations Human Settlements Programme. (2016). World cities report 2016: Urbanization and development. UN-Habitat.*
17. *Vaidyanathan, A. (2010). Rural–urban linkages and urban poverty in India. Indian Journal of Human Development, 4(2), 287–311.*
18. *Yadav, R. S. (2015). Impact of urbanization on slum growth in central India. Jamshedpur Research Review, 10(1), 55–63. https://jamshedpurresearchreview.com*
19. *Zérah, M. H. (2008). Splintering urbanism in India: Contrasting trends in public service reforms. Urban Studies, 45(2), 345–368. https://doi.org/10.1177/0042098007085961*